5. *Intensive Cotton Development Programme:* Distribution of certified seed	*1-10 years old verieties* 1. 25% of the cost of seed limited to Rs. 300/g. on mechanically delinted and Rs. 400/g. on acid delinted certified seeds. *10—15 years old varieties* Rs. 250/g. on mechanically/acid 2. delinted certified seeds.

6. *Technology Mission on Oilseeds, Pulses and Maize:*

TMOP is implementing two Centrally Sponsored Schemes of Oil Seeds Production Programme (OPP) 9 National Pulses Development Project (NPDP). in both the schemes assistance is being provided to the States as also to the Central Agencies like NSC & SFCI:—

OPP & NPDP

Distribution of certified Seeds	Rs. 300 per qtl. for the crops covered under these schemes.

B. Scheme-wise allocation of funds for distribution of certified seeds during 1997-98 for Rajasthan and Orissa is as follows:—

(Rs. in lakhs)

Schemes	*Rajasthan*	*Orissa*
1. ICDP—Rice	Not covered	650.00
2. ICDP—Wheat	15.40	Not covered
3. ICDP—Coarse Cereals	243.00	Not covered
4. Intensive Cotton Development Programme	49.28	4.20
5. SJDP	Not covered	12.30
6. OPP	130.00	100.00
7. NPDP	40.00	20.00

एक प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना

326. **श्री राम जेठमलानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में कपास की खेती हेतु भूमि सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसके बावजूद भी अन्य देशों में कपास के उत्पादन की तुलना में भारत में कपास का उत्पादन सबसे कम है;

(ग) यदि नहीं, तो विश्व में कपास की अधिकतम औसत और न्यूनतम उत्पादन-दर कितनी-कितनी है तथा भारत में इसकी औसत उत्पादन-दर कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने भारत में उपर्युक्त उत्पादन दर में वृद्धि करने के लिए किसी प्रौद्योगिकी मिशन को स्थापित करने का निश्चय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त मिशन कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है।

(ग) 1993, 1994 और 1995 के दौरान विश्व के प्रमुख देशों में कपास की अधिकतम, औसत और न्यूनतम उत्पादकता तथा भारत में इसकी औसत उत्पादकता निम्नानुसार है:—

उत्पादन (प्रति हैक्टेयर लिन्ट कि०ग्रा०)

	1993	1994	1995
अधिकतम	1300	1246	1509
औसत	551	588	582
न्यूनतम	231	209	125
भारत	281	308	301

स्रोतः खाद्य तथा कृषि संगठन।

(घ) और (ङ) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

फल और सब्जी उत्पादकों को ऋण प्रदान करने के लिए निगम की स्थापना

327. **श्री नागमणिः** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि फल और सब्जी उत्पादकों के लिए ऐसा कोई निगम नहीं है जो उन्हें ऋण उपलब्ध करवा सके;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निगम की स्थापना हेतु क्या प्रयास किए गए है; और

(ग) सरकार इस समय फल तथा सब्जी उत्पादकों को क्या सुविधा दे रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) जी नहीं, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम फल एवं सब्जी उत्पादकों की सहकारी समितियों को ऋण के रूप में सहायता मुहैया करा रहा है ताकि विपणन तथा प्रसंस्करण हेतु अवसंरचना का विकास किया जा सके। जनजातीय व कठिनाई वाले क्षेत्रों में ऋण के अतिरिक्त राजसहायता भी दी जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से सरल ऋण सहायता भी दे रही है ताकि फलों एवं सब्जियों हेतु फसल कटाई पश्चात् के रख-रखाव तथा विपणन संबंधी सुविधाएं सृजित की जा सकें। दूसरी तरफ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता मुहैया करा रहा है।

देश में फलों तथा सब्जियों की खेती को संवर्धित करने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है जिनके अन्तर्गत क्षेत्र विस्तारण अच्छे बीजों तथा पौध रोपण सामग्री की आपूर्ति, उत्पादकता में सुधार लाने के लिए आदान आपूर्ति, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता दी जा रही है।

(1) फलों का समेकित विकास

(2) सब्जियों के बीज का उत्पादन और उसकी आपूर्ति

(3) कन्दमूल फसलों का विकास

(4) खुम्बी विकास

(5) कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग।

नाबार्ड तथा विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगम भी फल तथा सब्जी उत्पादकों को सहायता दे रहे है।

Forecast of Normal Monsoon

328. DR SHRIKANT RAMCHANDRA JICKHAR:
SHRIMATI BASANTI SARMA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had made a forecast of normal monsoon for the current season;

(b) whether it is a fact that uptill now the monsoon have not been normal in several areas of the country;

(c) whether agriculture is likely to suffer due to this and is so; upto what extent; and